SHRI BHUPESH GUPTA: But the accident took place a long time back and I take it that whenever an accident of this nature takes place, it is the task of the Government to start an immediate enquiry and take steps with a view to starting the criminal proceedings. Have they been started and if so with what result?

SHRI ABID ALI: If the hon. Member is referring to the accident at Parasia, I may say that an enquiry committee was appointed, presided over by a High Court Judge and their report was received on the 22nd July, 1955 and we are at it and necessary proceedings will be started.

श्री कन्हैयालाल वो० वैद्य : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की जो खदानें देश के अन्दर हैं उनमें इस विषय में सुरक्षा के जो आवश्यक नियन्त्रण होने चाहिये उनका पालन किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : हमें तो यकीन है कि ये पालन किये जाते हैं । लेकिन जहां कहीं ऐसा मालूम होता है कि पालन नहीं किये जाते हैं तो मालिक को नोटिस दिया जाता है । अगर वे उस पर अमल नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

अमरीका के कृषि-विशेषज्ञों के दल का दौरा

*२३०. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **खाद्य और कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के ओहियो कृषि कालिज के डीन व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ अफसरों के एक विशेषज्ञ दल ने मई मास में हिमाचल प्रदेश का जो दौरा किया था, क्या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित था, और

(ख) इस दल ने कितने स्थानों का निरीक्षण किया और कृषि के विकास के लिये इसने क्या सिफारिशें की हैं ?

†[VISIT OF A TEAM OF AGRICULTURISTS FROM U.S.A.

*230 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the tour undertaken in Himachal Pradesh by an expert team consisting of the Dean of the Agricultural College at Ohio in the United States of America and some officers of the Indian Council of Agricultural Research was organised by the Government of India; and

(b) the number of places visited by the team and the recommendations made by it for the improvement of agriculture?]

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है ।

विवरण

युनाइटेड स्टेट्स टेकनिकल कोऑपरेशन मिशन इन इंडिया के साथ एक करार के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी संस्थाओं को सुदृढ करने का कार्यक्रम

कृषि सम्बन्धी शिक्षा, गवेषणा और विस्तार करने वाली संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सहायता देने के लिये, मार्च १९५५ में भारत सरकार ने युनाइटेड स्टेट्स टेकनिकल कोऑपरेशन मिशन इन इंडिया के साथ एक करार किया। इस कार्यक्रम के निम्न ध्येय थे :

(१) युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की कृषि संस्थाओं से विशेषज्ञों की सेवाओं के लाभ की और स्टाफ के कर्मचारियों के विनिमय की व्यवस्था करना;

(२) युनाइटेड स्टेट्स की चुनी हुई संस्थाओं में भारतीय स्टाफ के कर्मचारियों के

†English translation

उच्च प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराना; और

(३) संस्थाओं में पढ़ाई, प्रयोगशाला और खेतों में काम करने के लिये उपयोगी सामान को, जिसमें साधारणतया भारत में अप्राप्य टेकनिकल पुस्तकें और पत्रिकायें भी शामिल हैं, हासिल करना और देना।

२. इस योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रादेशिक आधार पर विविध संस्थाओं के हित के उद्देश्य से उनका पारस्परिक प्रबन्ध विकसित किया जायेगा। देश के विविध राज्य पांच प्रदेशों में बांट दिये गये हैं और युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के पांच बड़े लेण्ड ग्रांट कालिज और विश्वविद्यालयों के साथ प्रबन्ध करने का विचार किया जा रहा है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों से बनाए हुए उत्तर पश्चिम प्रदेश के साथ योग देना स्वीकार कर लिया है।

३. अप्रैल १९५५ में, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के डीन डाक्टर एल० एल० रुम्मेल और सहायक डीन डाक्टर टी० एस० सट्टन इस विचार से भारत में आये कि प्रारंभिक सर्वेक्षण कर इस प्रदेश के राज्यों की संस्थाओं में विद्यमान सुविधायें स्वयं देखें तथा इस कार्यक्रम के अधीन उनकी आवश्यकतायें निर्धारण करें। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने निम्न संस्थाओं का निरीक्षण किया :

(१) होरटीकलचरल रिसर्च स्टेशन।

(२) ब्रीट ब्रीडिंग स्टेशन।

(३) ब्रीट रस्ट रिसर्च स्टेशन।

(४) पोटेटो रिसर्च स्टेशन।

(५) सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी।

(६) बेसिक एग्रीकलचरल स्कूल।

४. इस सर्वेक्षण-दल ने यह सिफारिश की है कि उद्यान-शास्त्र के एक वैज्ञानिक को शिमले में ठहराया जाये। वह अपना अधिक समय हिमाचल प्रदेश में व्यतीत करेगा परन्तु प्रदेश के अन्य राज्यों को सलाह देने के लिये भी उपलब्ध होगा।

५. इस प्रदेश के अन्य राज्यों के लिए पांच अन्य विशेषज्ञों की भी सिफारिश की गई है। यद्यपि इन विशेषज्ञों को किन्हीं खास संस्थाओं में रखने का प्रस्ताव है तो भी उनकी जिम्मेदारी प्रादेशिक स्तर पर होगी। और उनके अपने मुख्य काम में अनुचित रूप से बाधा पहुंचाये बिना वे अन्य राज्यों को परामर्श के लिये उपलब्ध किये जायेंगे।

६. सर्वेक्षण-दल ने कृषि (पशु पालन) गवेषणात्मक और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को दो लाख डालरों के मूल्य के प्रयोगशाला और फार्म के उपयोगी सामान, टेकनिकल, पुस्तकें और पत्रिकायें इत्यादि देने की सिफारिश की है। जब विदेशी विशेषज्ञ संस्थाओं में आ जायेंगे उस समय राज्यों के साथ सलाह करने के बाद सामान की किस्म निश्चित की जायेगी।

इस प्रदेश में कृषि अनुसन्धान और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के उचित विकास के लिये जिस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है उन विषयों के खास प्रशिक्षण के लिए चुने हुए सात अधिकारी उस क्षेत्र से विदेश भी भेजे जायेंगे।

†[THE MINISTER FOR AGRICULTURE (DR. P. S. DESHMUKH): (a) Yes.

(b) A statement giving the requisite information is placed on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Programme for strengthening of Agricultural Institutions under an agreement with United States Technical Cooperation Mission in India.

In March 1955 the Government of India entered into an agreement with the United States Technical Cooperation Mission in India for providing assistance for the strengthening of institutions in the field of agriculture

†English translation.

engaged in education, research and extension. The programme envisages:

(i) Provision of the services of specialists from agricultural institutions in the U.S.A. and inter-change of staff personnel;

(ii) Provision of fellowships for Indian staff members for advanced training in selected institutions in the U.S.A.; and

(iii) Procurement and supply of equipment for class-room, laboratory and field operations, including technical books and journals, not ordinarily available in India.

2. Under this project inter-institutional arrangements will be developed by the Government of India on a regional basis. The various States in the country have been grouped into five regions and it is proposed to enter into arrangements with five of the principal Land Grant Colleges and Universities in the U.S.A. The Ohio State University has agreed to co-operate with the North-West Region comprising the States of Punjab, PEPSU, Himachal Pradesh and Rajasthan.

3. In April 1955 Dr. L. L. Rummell and Dr. T. S. Sutton, Dean and Assistant Dean, respectively of the Ohio State University came to India to make a preliminary survey and see personally the facilities now available in the institutions in the designated States in the Region and to determine their needs under this programme. In the Himachal Pradesh they visited the following institutions:

(1) Horticultural Research Station.
(2) Wheat Breeding Station.
(3) Wheat Rust Research Station.
(4) Potato Research Station.
(5) Soil Testing Laboratory.
(6) Basic Agricultural School.

4. The Survey Team has recommended the location of a Horticulture Scientist at Simla. He will devote major part of his time in the Himachal Pradesh State but would also be available for advice to the other States in the Region.

5. Five other experts have been recommended for assignment to the other States in the Region. Although it is proposed to locate the experts in specified institutions, their responsibility will be of a regional character and they would be made available for consultation by other States without unduly interfering with their primary assignments.

6. The Team has recommended the supply to agricultural (animal husbandry) research and educational institutions in the region of laboratory and farm equipment and technical books and journals worth 200,000 dollars. The type of equipment to be supplied will be determined in consultation with the States when the foreign experts are located in the institutions.

Seven selected officers from the region will also be sent abroad for specialised training in subjects in which such training is essential for the proper development of the agricultural research and educational institutions in the region.]

श्री नवाब सिंह चौहान : इस विवरण के अनुसार भारत सरकार ने सन् १९५५ में युनाइटेड स्टेट्स टेकनिकल कोओपरेशन मिशन इन इंडिया के साथ जो करार किया है उसके कार्यक्रम का ध्येय बतलाते हुये नं० (३) पर लिखा हुआ है कि "संस्थाओं में पढ़ाई, प्रयोगशाला और खेतों में काम करने के लिये उपयोगी सामान को, जिसमें साधारणतया भारत में अप्राप्य टेकनिकल पुस्तकें और पत्रिकायें भी शामिल है।" इस तरह से भारत सरकार ने अब तक कितना सामान दूसरे देशों से उपलब्ध किया है जो भारत में नहीं मिलता ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता अभी कुछ सामान आया हुआ है क्योंकि फिलहाल तो एक्सपर्टस यहां पर आ

रहे हैं, वे सूबो में घूम रहे है और सस्थाओ को कौटेक्ट कर रहे है और देख रहे है । उसके बाद वे यह तय करेंगे कि क्या सामान आना चाहिये ।

श्री नवाब सिंह चौहान . नम्बर २ मे लिखा है कि "देश के विविध राज्य पाच प्रदेशो मे बाट दिये गये हैं और युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका के पांच बडे लैंड ग्रान्ट कालिज और विश्वविद्यालयो के साथ प्रबन्ध करने का विचार किया जा रहा है ।" एक रीजन हिमाचल प्रदेश बनाया हुआ है, ४ अन्य प्रदेश कौन है कृपा कर मंत्री महोदय बतलावे ।

DR. P. S. DESHMUKH: The regions are:

(1) Northern, which consists of Uttar Pradesh, Madhya Bharat, Bhopal and Vindhya Pradesh;

(2) North-Western, consisting of the Punjab, PEPSU, Rajasthan and Himachal Pradesh;

(3) Eastern, comprised of Assam, West Bengal, Bihar and Orissa;

(4) Central, consisting of Bombay, Madhya Pradesh, Hyderabad, Saurashtra and Kutch;

(5) Southern, made up of Madras, Mysore, Travancore-Cochin and Coorg.

श्री नवाब सिंह चौहान . क्या इन प्रदेशो में भी अब कार्य प्रारम्भ होने की आशा की जा सकती है जैसा कि हिमाचल प्रदेश मे हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मं समझता हूं कि एक छोड़ कर सभी तरफ़ एक्सपर्ट्स आये हुये है और इन संस्थाओं को देख रहे है ।

श्री नवाब सिंह चौहान : नम्बर ६ में दो लाख डालर के एक ग्रान्ट का जिक्र किया है । यह केन्द्रीय सरकार देगी या और कही से प्राप्त होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो यू० एस० ए० से मिलेगा ।

यात्रा स्थानों का विकास

*२३१. **श्री नवाब सिंह चौहान** क्या परिवहन मत्री ११ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रा स्थानों के विकास की अल्पकालीन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मे कितने स्थान इस प्रयोजन के लिये चुने जा चुके हैं ; और

(ख) इस योजना पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

†[DEVELOPMENT OF TOURIST CENTRES

*231. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for TRANSPORT be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 187 on the 11th March, 1955 and state:

(a) the number of places in each State selected for being developed as tourist centres under the short term plan; and

(b) the expenditure likely to be incurred on the plan?]

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि पर्यटन की उन्नति के लिये एक पंचवर्षीय योजना होगी जो कि इस दूसरी आम पंचवर्षीय योजना का एक अंग समझी जायेगी । फिर भी सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार कुछ

†English translation.